

प्रेषक,

महिमा,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों की 02(दो) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग पौड़ी के पत्रांक-1505/33(208) भवन पर्व/08 दिनांक 20-03-08 के क्रम में एवं शासनादेश सं0-1538/111-2/07-08(प्रा0आ0)/2007 दिनांक 13-07-07 के सदर में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13-07-07 द्वारा संलग्नक के क्र0-1 व 2 पर स्वीकृत 02 कार्यों की स्वीकृति को निरस्त करते हुये मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के रूपये 346.01 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 249.17 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-05 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. इन कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु निर्गत की गई धनराशि रु0 01.00 लाख को तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों का जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 4- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- 5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 6- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।
- 8- कार्य कराने से पूर्व स्थल उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेता के साथ भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा ले, निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 9- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर व्यय कदापि न किया जाय।

*Handwritten signature*

- 10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- 11- उक्त कार्यो हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा ।
- 12- कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता का होगा। समयबद्धता रूप से कार्य करने हेतु संबंधित अधिकारी/ निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते हैं ।
- 13- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि० 31-03-09 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय । कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
- 14- आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा और उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही उक्त कार्यो पर आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।
- 15- व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में ही पूर्णतः कर लिया जायेगा। व्यय न हो पाने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशाली अभियन्ता का होगा।
- 16- कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्यभवन-13-पूल्ड आवास योजना-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा
- 17- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 936/XXVII(2)/2007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:- 02 कार्यो की सूची।

भवदीय  
/ (महिमा)  
अनु सचिव

संख्या:- 4045 (1)/111(2)/08-08(प्रा.आ.)-2007 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
/ (महिमा)  
अनु सचिव

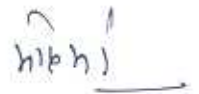


शासनादेश संख्या-4045/111(2)/08-08(प्रा.आ.)/07 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5
1.	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक रिखणीखाल में निरीक्षण भवन का निर्माण।	189.67	135.97	0.50
2.	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अधारियाखाल में निरीक्षण भवन का निर्माण।	156.34	113.20	0.50
	योग:-	346.01	249.17	01.00

(रुपये एक लाख मात्र)



(महिमा)  
अनु सचिव